



राज्य विधान मंडल में राज्यपाल का अभिभाषण

28-01-2021

माननीय सभापति, कर्नाटक विधान परिषद,
माननीय अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा
कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री और
कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण,

मैं वर्ष 2021 के लिए राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि पिछला वर्ष कोविड -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महामारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हम निष्पक्षता के साथ विकास के रास्ते पर लौट आएंगे। मैं कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का यह अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

मेरी सरकार ने कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का भरसक प्रयास किया है और हमने इस संकट का इस्तेमाल देश में अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना बनाने और पीपीई किट और वेंटीलेटर के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत ने दो टीकों का उत्पादन किया है और विदेशों में इन टीकों का निर्यात भी किया है। 16 जनवरी को विश्व टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक सक्षम नेता के रूप में सम्मानित प्रधानमंत्रीजी ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीके को उत्तरोत्तर सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

सभी सरकारी एजेंसियों जैसे डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, राजस्व, पंचायत पदाधिकारियों आदि ने दिन-रात काम किया और जनता की अनावश्यक और अवांछित आवाजाही पर रोक लगाते हुए महामारी के फैलने पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आपातकालीन सेवाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन की सुविधा प्रदान की।

मेरी सरकार ने कोविड-19 से संबंधित काम निभाने के दौरान मृत्यु होने के मामले में, सरकारी कर्मचारियों को 30 लाख रुपये के अत्यधिक मुआवजे की घोषणा की है।

महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद मेरी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। इसके अलावा, हम दूध उत्पादन में दूसरे, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (विकास, इकिटी और सततता) में चौथे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स (नीति आयोग 2019) में छठे और ग्यारह (11) सतत विकास लक्ष्यों में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे आगे हैं। हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत और देश के आईटी निर्यात में चालीस प्रतिशत (40%) का योगदान करते हैं। हमारे राज्य ने मत्स्य पालन क्षेत्र में दो दशमलव नौ प्रतिशत (2.9%) की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है और दलहनों के सबसे अधिक उत्पादन में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है।

मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, पी एम केयर्स और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कोष से पांच सौ छब्बीस (526) करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मेरी सरकार ने आरटी-पीसी आर तकनीक का उपयोग करके 80 लाख से अधिक लोगोंकी कोविड जाँच की है जो प्रति लाख जनसंख्या पर जाँच किए गए व्यक्तियों के मामले में देश में सबसे अधिक है।

मेरी सरकार ने एक दशमलव छत्तीस (1.36) लाख कोविड रोगियों के मुफ्त उपचार को मंजूरी दी है और इस पर दो सौ अड़तालीस (248) करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विशेष रूप से कोविड के दौरान, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

मेरी सरकार ने दो सौ अड़तालीस (248) राज्य सरकार कल्याण संस्थानों में नौ हज़ार नौ सौ चौरानवे (9,994) निवासियों और 182 केंद्र सरकार कल्याणकारी संस्थानों के आठ हज़ार नौ सौ उन्नीस (8,919) निवासियों को दासोह योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया है।

मेरी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पोषण आहार के नब्बे (90) लाख पैकेट उपलब्ध कराए और रेलवे के साथ मिलकर उनके उनके गृह राज्यों तक की सुरक्षित यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं के साथ विशेष श्रमिक गाड़ियों की व्यवस्था भी की।

कोविड-19 संकट के दौरान तिरसठ लाख उनसठ हज़ार (63,59,000) लाभार्थियों को पाँच हज़ार तीन सौ बहत्तर (5372) करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी जिसमें किसान, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ऑटो चालक, बुनकर नाई शामिल थे। इसके अतिरिक्त

कर्नाटक के सभी बीपीएल कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। सोलह हज़ार नौ सौ चौबीस (16,924) कलाकारों/लेखकों को तीन दशमलव अड़तीस (3.38) करोड़ रुपये की एक बारगी सहायता प्रदान की गयी। निर्माणकर्ता निगम की ओर से सोलह दशमलव पैंतालीस (16.45) लाख कार्मिकों को आठ सौ चौबीस (824) करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

मेरी सरकार ने कोविड-19 संकट से प्रभावित ग्यारह हजार सात सौ सत्तर (11,770) चमड़ा कारीगरों में से प्रत्येक को 5000 रुपये जारी किए।

मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,020 करोड़ रुपये से इक्यावन (51) लाख किसानों को, प्रति किसान 2000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है।

मेरी सरकार ने इक्सठ हजार तीन सौ उन्यासी (61,379) मेट्रिक टन धान, एक दशमलव तिरानवे (1.93) लाख मेट्रिक टन रागी और नौ हज़ार दो सौ छप्पन (9,256) मेट्रिक टन ज्वार की खरीद करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया है।

उद्योगों सहित बिजली उपभोक्ताओं को भी विभिन्न राहतें और प्रोत्साहन दिए गए हैं।

राज्य में फंसे पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 37 देशों के छह हज़ार सात सौ अस्सी (6,780) विदेशी पर्यटकों को अपने देश लौटने की सुविधा प्रदान की गई।

मेरी सरकार ने **विज़न-2030** तैयार किया है जिसमें नवोन्मेषी रणनीतियों और पहलों को शामिल किया गया है ताकि राज्य को भूख और एनीमिया से मुक्त और साथ ही लिंग-अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मेरी सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छियालीस हजार तीन सौ अठहत्तर (46,378) जल संचयन संरचनाएँ बनाई हैं जिससे एक दशमलव अठासी (1.88) लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाई गई हैं, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्र में दो दशमलव छिहत्तर (2.76) लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

मेरी सरकार ने पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत दो दशमलव चार (2.4) लाख मामलों को दर्ज करके एक दशमलव चार (1.4) लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। खरीफ 2019-20 के संबंध में तीन दशमलव ग्यारह (3.11) करोड़ में से दो सौ छियानबे (296) करोड़ का दावा, बीमा कंपनियों द्वारा निपटा दिया गया है।

खरीफ 2020 में सर्वेक्षण किए गए दो दशमलव दस (2.10) करोड़ भूखंडों में से, लगभग 80 लाख भूखंडों को, किसानों द्वारा स्वयं अपलोड किया गया था। कर्नाटक में किसान के सक्रिय सहयोग द्वारा फसल सर्वेक्षण डाटा का डिजिटी करण करने की भारत सरकार ने प्रशंसा की है।

तेईस हजार चौंसठ (23,064) हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों का विस्तार किया गया है। बत्तीस हजार आठ सौ अठहत्तर (32,878) हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित है। तीस हजार चार सौ

अड़तीस (30,438) हेक्टेयर में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन किया गया है। 1089 फसलेत्तर प्रबंधन इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

मेरी सरकार ने 2020-21 से 2026-27 तक राज्य के 21 जिलों में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए अभिनव विकास के माध्यम से कृषिपुनरुत्थान के लिए पनधारा पुनर्जीवित करने की विश्व बैंक की परियोजना को 600 करोड़ रुपये के बजट के साथ अनुमोदित किया है।

मेरी सरकार ने चार हजार पांच सौ चालीस (4,540) करोड़ रुपये की आर्थिक प्रगति के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल एक हजार एक सौ चौरानवे (1,194) लाख श्रम दिवस सृजित किए हैं।

मेरी सरकार ने 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रामनगर, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु, मांड्या, कोप्पल, बेलगावी और उडुपी जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

मेरी सरकार ने 142 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बल्लारी, चित्रदुर्गा और हुब्बली-धारवाड़ के शहरी स्थानीय निकायों में पीपीपी आधार पर अपशिष्ट जल का उपचार शुरू किया है।

मेरी सरकार ने फ्लाई ऐशा निपटान नीति पेश की है जिसके परिणाम स्वरूप ताप विद्युत स्टेशनों में शत प्रतिशत (100%) राख का उपयोग हुआ है और इससे पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है।

मेरी सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन इंडेक्स टूल किट विकसित की है और राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चौदह हजार नौसो इकहत्तर (14,971) मेंगा वाट्स की संचयी स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक देश में अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर है।

मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत, चौदह हजार तीन सौ बीस (14,320) गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया है।

मेरी सरकार ने, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों और उन सभी किसानों को, जिनके आईपी सेट 10 एचपी से नीचे हैं, मुफ्त बिजली की आपूर्ति, सुनिश्चित करने के लिए के ग्यारह हजार दो सौ पचास (11,250) करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है।

मेरी सरकार ने शिक्षक और अभिभावक हेल्पलाइन, शिक्षा मित्र और मक्कलवाणी यू-ट्यूब चैनल का लॉन्च किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। स्कूल के पाठ्यक्रम को संक्षिप्त शैक्षणिक अवधि के लिए, फिर से बनाया गया है।

मेरी सरकार ने पूर्व छात्रों, संघों और विभिन्न संगठनों से दान एकत्र करने के लिए माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन (नन्ना शाले नन्ना कोडुगे) नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है। आज तक, जन-प्रतिनिधियों, समुदाय के गणमान्य लोगों और स्वयंसेवी संगठनों ने, 1,500 स्कूलों को इसके अंतर्गत अपनाया है।

मेरी सरकार ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) की शुरुआत करके कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया है जो छात्रों को वेब-आधारित प्लेटफॉर्म, ऐप और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से, विषय सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देगा।

मेरी सरकार ने 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत **चिक्काबल्लापुर, हावेरी, यादगिरी** और **चिक्कमगलूर** जिलों में से, प्रत्येक ज़िले में 325 करोड़ रुपये की लागत से, नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं।

मेरी सरकार ने कल्याण कर्नाटक के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कलबुरगी में 300- बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल श्री जयदेव कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य को शुरू किया है।

मेरी सरकार ने 2020-21 के लिए कल्याण-कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड को एक हजार एक सौ बत्तीस (1132) करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया है।

इस क्षेत्र का एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से कल्याण-कर्नाटक मानव संसाधन, कृषि और सांस्कृतिक संघ की स्थापना की गई है। 100 करोड़ रुपये जारी कर दिये गए हैं।

मेरी सरकार ने बसव कल्याण में अनुभव मंटप का निर्माण करने के लिए 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं ताकि उसे एक अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

मेरी सरकार ने बैंगलुरु शहर के प्रशासन के लिए एक पृथक विधान के रूप में बृहत बैंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम बनाया है और बैंगलुरु में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंगलुरु मिशन 2022 शुरू किया है। बैंगलुरु शहर में बुनियादी ढांचे और विकासात्मक कार्यों के लिए आठ हजार पंद्रह (8,015) करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं।

मेरी सरकार ने नव नगरोत्थान कार्यक्रम के तहत एक हजार साठ (1,060) करोड़ की लागत के नालों के निर्माण को मंजूरी दी है। बीबीएमपी के तहत हाल ही में शामिल किए गए 110 गांवों को भूमिगत जल निकासी सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। नगरोत्थान के तीसरे चरण के तहत 263 शहरी स्थानीय निकायों में 1598 कार्य पूरे हो चुके हैं।

मेरी सरकार ने चौदह हजार नौ सौ नौ (14,909) आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 256 एकड़ के क्षेत्र में 35 आवास परियोजनाएं शुरू की हैं।

मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत तीन दशमलव पंद्रह (3.15) लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है और अमृत योजना के तहत एक हजार छे सौ अस्सी (1680) करोड़ रुपये की राशि के 306 कार्य पूरे किए गए हैं।

मेरी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के उपयोग के तहत 400 करोड़ रुपए की 162 परियोजनाएँ पूरी की और 7 स्मार्ट शहरों में, छह हजार दो सौ तेंतीस (6233) करोड़ की लागत वाली, 345 परियोजनाओं पर काम अभी चल रहा है।

विश्व बैंकसे सहायता-प्राप्त कार्यक्रम के तहत, बेलगावी, कलबुर्गी और हुब्बली-धारवाड़ के समस्त निगम क्षेत्रों में 24 घंटे जल की आपूर्ति के लिए 2848 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से काम किया गया है। एक हजार छे सौ दो (1602) करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, राज्य भर में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजनाएँ और 1103 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 24 भूमिगत जल निकासी परियोजनाओं पर भी काम किया गया है।

मेरी सरकार ने निर्माणाधीनमेट्रो कार्यों को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी है। चरण 2 और चरण 2A का काम प्रगति पर हैं और वर्ष 2022 तक 75 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाने का लक्ष्य है।

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) द्वारा इस वर्ष के दौरान वन नेशन वन कार्ड का प्रयोग करते हुए स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली स्थापित की जाएगी।

बेंगलुरु में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर पंद्रह हजार सात सौ सड़सठ (15,767) करोड़ रुपये की लागत से बेंगलुरु उप-नगरीय रेल परियोजना का अनुमोदन किया है।

बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को इस वर्ष 6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

मेरी सरकार ने तीन हजार चार सौ उनसठ (3459) किलोमीटर सड़क और 202 पुलों के निर्माण के लिए चार हजार सात सौ पचपन (4755) करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों में 447 किलोमीटर की कंक्रीट सड़कें बनाई जाए, एक विशेष विकास योजना के तहत 588 किलोमीटर की सड़क का विकास हो तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण रास्ता अभिवृद्धि योजना के तहत, 143 किलोमीटर सड़क का विकास कार्य पूरा किया जाए।

कुल नौ हजार छे सौ एक (9,601) किलोमीटर जिला राजमार्गों को राज्य राजमार्गों के रूप में और पंद्रह हजार पांच सौ दस (15510) किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को प्रमुख जिला सड़कों के रूप में उन्नत किया गया है। सचलता को बहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,850 कार्य शुरू किए हैं।

उत्तर कन्नड़ जिले के कासरगोड टोंक, होन्नावर तालुक में, सरकारी-निजी भागीदारी के तहत पत्तन विभाग की पट्टेवाली भूमि में 525 करोड़ रुपये वाले रक्षित पत्तन का निर्माण शुरू हो गया है।

एक समर्पित एयरोस्पेस पॉलिसी को आरंभ करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य है।

बीदर एयरपोर्ट का परिचालन 07.02.2020 को किया गया है। शिवमोगा जिले में 385 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में सत्ताईस दशमलव चौरासी (27.84) करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौसेना एयर बेस के

समीप सिविल एन्कलेव के विकास का काम प्रगति पर है। विजयापुर एयरपोर्ट को 220 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री की एक लाख आवास योजना के तहत, छियालीस हजार चार सौ निन्यानवे (46,499) मकानों में से इकतीस हजार तीन सौ बयासी (31,382) मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। स्लम सुधार कार्यक्रम के तहत, 150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत चार हजार चार सौ साठ (4,460) करोड़ रुपये की लागत से अवसंरचना सहित तिरासी हजार एक सौ उन्नीस (83,119) मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। राजीव आवास योजना के तहत, उन्नीस हजार आठ सौ सत्तानवे (19,897) मकानों के निर्माण के लिए एक हजार तीस (1,030) करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इनमें से अठारह हजार पांच सौ सत्तर (18,570) मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। एक हजार आठ सौ अठारह (1,818) स्लम क्षेत्रों में तीन दशमलव छतीस (3.36) लाख परिवारों को हक-पत्र जारी किए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में चौहत्तर हजार पांच सौ चौहत्तर (74,574) साइट और ग्रामीण क्षेत्रों में, अड़तालीस हजार एक सौ इक्सठ (48,161) साइट वितरण के लिए तैयार हैं।

कारखाना अधिनियम के तहत एक बार में 15 साल तक लाइसेंस के पंजीकरण / नवीनीकरण की अनुमति देकर श्रम कानूनों का सरलीकरण किया गया है और स्वचालित नवीनीकरण प्रणाली शुरू करके लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है। महिला कर्मचारियों को चौबीसों घंटे कारखानों में काम करने की अनुमति देने के

लिए अधिसूचना जारी की गई है और प्रति तिमाही ओवरटाइम काम के घंटे की संख्या 75 से बढ़ाकर 125 घंटे की गई है।

मेरी सरकार ने पिछड़े वर्गों के छब्बीस हजार पांच सौ बावन (26,552) लोगों के लाभ के लिए स्व-रोजगार योजनाओं, अरिवु-शिक्षा ऋण और गंगा कल्याण सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर 215 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए सत्रह हजार आठ सौ तिरसठ (17,863) करोड़ रुपये, और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सात हजार सात सौ चौवन (7,754) करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विभिन्न निगमों के माध्यम से पंद्रह हजार आठ सौ सैंतीस (15,837) अजा/अजजा लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। भूमि स्वामित्व योजना के तहत, लाभार्थियों के लिए तीन हजार इक्सठ (3,061) एकड़ भूमि खरीदी और वितरित की गई है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर्नाटक आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी के आवासीय विद्यालयों में एक हजार इक्कीस (1,021) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।

मेरी सरकार ने कर्नाटक इनोवेशन अथॉरिटी की स्थापना की है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से स्थापित किया गया है ताकि नवाचार को समन्वित किया जा सके, निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, रणनीति तैयार की जा सके और ब्रांडिंग को बढ़ाने और वैश्विक नवाचार गठजोड़ स्थापित करने की, नई पहल का प्रस्ताव किया जा सके।

मेरी सरकार ने बैंगलुरु से बाहर आईटी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए नई आईटी नीति 2020-25 की घोषणा की है। वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट बैंगलुरु टेक समिट का आयोजन, एक आभासी मंच पर सफलतापूर्वक किया गया जिसमें 25 विदेशी देशों की भागीदारी थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री और स्विस संघ के उपाध्यक्ष की आभासी भागीदारी थी।

मेरी सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक **विशेष इंटर्नशिप अभियान** शुरू किया जो स्नातकोत्तर युवाओं से अभिनव समाधान की मांग करता है। अब तक 35 कार्य पूरे हो चुके हैं और 50 प्रगति पर हैं।

मेरी सरकार ने विधानसौधा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक ई-ऑफिस सुविधा का विस्तार किया है। बैंगलुरु में, जनसेवक सेवा शुरू की गई और नागरिकों को बयालीस हजार (42,000) से अधिक सरकारी सेवाओं घर बैठे दी गई। ग्राम स्तर पर सभी नागरिक केंद्रित गतिविधियों के लिए ग्राम प्रथम को एकल बिंदु सहायता केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

कर्नाटक वन विभाग के सहयोग से कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने जंगल की आग के कारण जंगल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, एक फारेस्ट फायर मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है।

पूरे बजटीय आवंटन की निगरानी के लिए सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के सहयोग से योजना विभाग ने अवलोकन पोर्टल शुरू किया गया। 20,000 कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा 1,800 योजनाओं की निगरानी की गयी।

मेरी सरकार ने प्रति वर्ष 10% औद्योगिक विकास को बनाए रखने के मिशन के साथ नई औद्योगिक नीति 2020-2025 पेश की है जिसमें 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना, 20 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार के लिए इको-सिस्टम को सक्षम बनाना शामिल है।

मेरी सरकार ने तिरपन हजार दो सौ पंचानवे (53,295) करोड़ रुपये की निवेश क्षमता के साथ 366 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य इस वर्ष के दौरान एक दशमलव चौवन (1.54) लाख नौकरियां पैदा करना है।

उद्योगों को भूमि की आसान उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 में संशोधन किया है।

मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 1763 इकाइयां स्थापित की हैं। मेगा और बड़े उद्योगों को वैट / एसजीएसटी / ब्याज मुक्त क्रण प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मेरी सरकार ने नई रेत नीति-2020 लागू की, जिसमें धाराओं, तालाबों और झीलों में उपलब्ध रेत को बेचने का प्रावधान किया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए कर्नाटक स्टोन रेगुलेशन क्रशर एकट -2011 में संशोधन किया गया है।

परिवहन विभाग ने 4 करोड़ रुपये की लागत से बेसकोम (BESCOM)के माध्यम से बैंगलोर में 126 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।

कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक स्कैप बस को स्त्री टॉयलेट नामक एक सुसज्जित महिला शौचालय में बदल दिया | जिसने इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है।

मेरी सरकार ने नई पर्यटन नीति 2020-25 आरंभ की है। नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 26 मार्गों की परिकल्पना की गई है। कर्नाटक राज्य में 844 स्मारकों में से, बैंगलोर क्षेत्र के 105 स्मारकों की 3 डी मैपिंग और लेजर स्कैनिंग की गई है।

मेरी सरकार रामनगर जिले में वीरपुरा स्थित श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी के जन्म स्थल को एक सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

रामनगर जिले के बानंदुर गाँव स्थित श्री श्री बालगंगाधरनाथ स्वामीजी के जन्म स्थान को भी एक सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मेरी सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एस निजलिंगप्पा के चित्रदुर्गा जिले में स्थित जन्म स्थान को विकसित करने की योजना बनाई है।

मेरी सरकार ने 25 करोड़ रुपये की लागत से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के परिसर में नादप्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। 2019-20 के दौरान, 603 सब इंस्पेक्टर और तीन हजार पांच सौ छियासठ (3566) पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए, सब इंस्पेक्टरों के 653 पदों और पुलिस कांस्टेबलों के छह हजार छह सौ पचासी (6,685) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस विभाग में सभी भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत (2%) कोटा निर्धारित किया गया है जिससे पुलिस बल में शारीरिक फिटनेस और खेल-कूद को बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक हजार पांच सौ सड़सठ (1567) कर्मियों की भर्ती शुरू की है। अग्निशमन बल ने दो हजार इक्यावन (2,051) मानव जीवन और 482 करोड़ रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्ति बचाई है। सरकार ने 25 करोड़ रुपये की लागत से 90 मीटर ऊँचाई के एरियल लैडर प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है। यह आग बुझाने और बचाव अभियान के लिए देश की सबसे ऊँची सीढ़ी होगी। मेरी सरकार ने आपदा प्रबंधन के उन्नत बचाव उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

मेरी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। समाज, विशेष रूप से युवाओं पर ड्रग्स के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन और उनकी खपत की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपने प्रयासों को समन्वित किया है। चार हजार छियासठ (4,066) मामले दर्ज किए गए और 34 करोड़ रुपये की नारकोटिक्स जब्त की गई।

राज्य भर से संकटपूर्ण कॉल पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए, 80 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय कमांड केंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है।

पुलिस गृह-2025 योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों में 10,000 पुलिस छार्टर बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बेंगलुरु के मड़ीवाला में 30 करोड़ रुपये की लागत से **फोरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर** का निर्माण किया गया है।

अगस्त से अक्टूबर 2020 के दौरान बाढ़ की तीन घटनाओं से निपटने के लिए मेरी सरकार ने तेजी से और अच्छी तरह से समन्वय किया। फायर और इमर्जेंसी सर्विसेज और एसडीआरएफ के अलावा, 16 एनडीआरएफ टीमों, 4 आर्मी कॉलम तैनात किए गए थे। साथ ही, 4 आईएएफ हेलीकॉप्टरों को तैयार रखा गया था। संयुक्त बचाव दल द्वारा लगभग पांच हजार सोलह (5,016) लोगों को बचाया गया। लगभग बावन हजार दो सौ तिरपन (52,253) बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण देने के लिए 313 राहत शिविर खोले गए। सत्ताईस हजार सात सौ तिहत्तर

(27,773) बाढ़ प्रभावित परिवारों में प्रत्येक को 10,000 रुपये की राहत दी गई है, जिसमें से 6,200 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हैं।

मेरी सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 5 लाख रुपये, बड़ी क्षति वाले मकानों के लिए 3 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग संरचनात्मक रूप से सुरक्षित मकान का निर्माण करें जो पुनः बेहतर निर्माण के सिद्धांत के अनुरूप हो। आवास सहायता का महत्वपूर्ण हिस्सा मेरी सरकार द्वारा वहन किया गया है। आवास सहायता के लिए 152 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

मेरी सरकार ने नौ लाख बाईस हजार छे सौ पांच (9,22,605) बाढ़ प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे 710 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की है। सड़कों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की मरम्मत के लिए मेरी सरकार ने 423 करोड़ रुपये जारी किए हैं। कुल मिलाकर, बाढ़ राहत के लिए एक हजार तीन सौ पैंतालीस (1,345) करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, मेरी सरकार ने वाणिज्यिक करों के माध्यम से तीस हजार चार सौ सड़सठ (30,467) करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क विभाग के माध्यम से सोलह हजार सात सौ अठासी (16,788) करोड़ रुपये एकत्र किए हैं ताकि राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिए आसानी से वित्तपोषण सुनिश्चित हो सके।

मेरी सरकार ने राज्य में सभी विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) भी लागू की है, ताकि नागरिकों को उनके कर का भुगतान ऑनलाइन करने में मदद मिल सके।

मैं, वर्तमान चुनौतियों से निपटने और कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न नवाचार उपायों के बारे में वाद-विवाद करने और उस पर चर्चा करने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

जय हिन्द !

जय कर्नाटक !